CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 27 अंक- 263 रायपुर, बुधवार 16 अक्टूबर 2024 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

जम्मू-कश्मीर में उमर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

हरियाणा की कमान नायब सैनी के हाथों में ही रहेगी

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई।

मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद अहमद राणा, रफियाबाद से जावेद अहमद डार, डीएच पोरा से सकीना इट्टू और नौशेरा से सुरिंदर कुमार चौधरी को भी एलजी सिन्हा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सुरिंदर चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सुरिंदर चौधरी ने नौशेरा से भाजपा के रविंदर रैना को हराया है। छंब विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में जगह दी गई।

सुरिंदर चौधरी डिप्टी सीएम

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। वहीं, जेके एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, क नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता यहां मौजूद रहे। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है। लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं, जेक पीसीसी प्रमुख ने कहा और

विधायक दल की बैठक में लगी मुहर

हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी होंगे। पंचकूला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी का नाम रखा था। सैनी गुरुवार को पंचकूला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह रात को चंडीगढ़ के ललित होटल में रुकेंगे। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा राजभवन में मीटिंग लेंगे। भाजपा ने अपने सभी 48 विधायकों को अगले दो दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश जारी किए हैं। होटल ललित और हरियाणा राजभवन सेक्टर-6 में काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं होटल हयात में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड और पुड्डुचेरी के सीएम शामिल हैं।

कैबिनेट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

रायपुर, 16 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। राज्य सरकार कुछ नए फैसले जनता के बीच पेश कर सकती है।

बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। इसके कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उप समिति ने भेजा था। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में बैठक में की गई। इस मीटिंग खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई थी।

इस साल 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया है। बैठक धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किए जाने पर बात हुई। मंत्रियों ने कहा कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ही इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बुधवार को इस पर सरकार फैसला स्पष्ट करेगी। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है।

राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली का उपहार दिया है. कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है. अब कर्मचारियों को 4त्न बढ़ाकर महंगाई भत्ता दिया जाएगा. कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ एक अक्टूबर से मिलेगा.

बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान डीए दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसपर मुख्यमंत्री साय ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री ने आज हेलीपैड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि आज एक बड़ा गौरव का विषय है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दीपावली आ रही है राज्य के कर्मचारियों को 46प्रतिशत डीए मिल रहा है. उसे केंद्र के सामान करते हुए 4प्रतिशत डीए बढ़ा रहे है, अब

मुख्यमंत्री ने की घोषणा

शिक्षक मोर्चा में कभी खुशी कभी गम का माहौल 24 को सामूहिक अवकाश लेकर रहेंगे हड़ताल पर

मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर से 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चाविके प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा ,मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा है कि यह घोषणा कभी खुशी कभी गम के रूप में है, शिक्षक व कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दीपावली के पूर्व दिया गया है जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को देय तिथि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था, यह निर्णय नहीं लिया गया जिससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है,,,साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है जिसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं। 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना रेगुलर डीए दिया जाना है इसका दीपावली के पूर्व दिया जाना स्वागतेय है। शिक्षक मोर्चा का हड़ताल पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए घोषित है, आंशिक विषय लंबित 4त्न मंहगाई भत्ता की घोषणा की गई है, अतः मुख्य विषय पर निर्णय नही लिए जाने तक 24 का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल जारी रहेगा।

ब्रेकिंग न्यूज

प्रधानमंत्री ने एनएसजी के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के स्थापना दिवस के मौके पर इस आकस्मिक तैनाती बल के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश की सुरक्षा में इसके योगदान पर हर देशवासी को नाज है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एनएसजी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत उन सभी एनएसजी कर्मियों को सलाम करता है, जो राष्ट्र की रक्षा करने में अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं।खतरों के खिलाफ हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। उनकी वीरता और उनके पेशेवराना अंदाज का कोई सानी नहीं है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण विरोधी क्रिया कलापों में इसके जवान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग करते हैं। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का उपयोग किया जाता है।

शंघाई सहयोग संगठन सम्मलेन में जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले दी बधाई फिर जमकर लगाई लताड़

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन सम्मलेन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को उसके ही घर में लताड़ लगा दी। सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर ने सबसे पहले पाकिस्तान को इस साल स्ष्टह्र की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और कहा कि भारत ने सफल स्ष्टह्र अध्यक्षता के लिए पूरा समर्थन दिया है। इसके बाद जयशंकर नेशंघाई सहयोग संगठन सम्मलेन में पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अगर दो देशों के बीच सीमा पार गतिविधियाँ उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद जैसी नकारात्मक तत्वों से भरी हों, तो यह व्यापार, कनेक्टिविटी और आपसी संबंधों को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकतीं।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया है।

चुहिया- हां जी, ठीक किया है सम्मानजनक रहने का तरीका तो यही है...!

चुनाव के ऐलान के बाद महायुति सरकार ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड, कहा- लाडकी बहिन जैसी योजनाएं से विरोधी भी चकित

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान %महायुति% सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। आरपीआई (ए) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार की लाडकी बहिन जैसी योजनाओं को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से हमारे विरोधी चकित हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार परिवर्तनकारी योजनाएं लेकर आयी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में महायुति के संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन विकास विरोधी दूरदृष्टि से काम करता है। यूबीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए, महायुति नेताओं ने कहा कि पूर्व सीएम राज्य में परियोजनाओं में देरी कर रहे थे, जबकि विपक्षी दल कहानी को घुमाने में व्यस्त थे। इस बीच, मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे की

'6जी' मानकों व विनियमों में सभी के लिए समावेशिता सुनिश्चित होनी चाहिए : सिंधिया

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि 6जी से संबंधित मानकों तथा नियमों से सभी के लिए समावेशिता और सामर्थ्य सुनिश्चित होना चाहिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) में अंतरराष्ट्रीय 6जी संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर सिंधिया ने कहा कि चूंकि 6जी के लिए मानक तय किए जा रहे हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग में अपनी सिद्ध क्षमताओं को देखते हुए भारत के पास जबरदस्त अवसर हैं।

मंत्री ने कहा, '' हमारे 6जी मानक जो अभूतपूर्व गति, कम विलंबता और परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों की विशेषता रखते हैं...सभी के लिए समावेशी, सुलभ व किफायती होने चाहिए और केवल तभी यह समग्र मानवता के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।'' सिंधिया ने 6जी अवसर का लाभ उठाने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, '' जैसा कि हम विनियामक वातावरण तैयार करते हैं, भारत के पास विनियमनों के निर्माण में योगदान देने की जबरदस्त क्षमता है।' भारत में एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित) स्नातकों की एक बड़ी संख्या है। इसकी प्रौद्योगिकी प्रगति एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है क्योंकि दुनिया 6जी की ओर बढ़ रही है। मंत्री ने कहा, '' दुनिया के

केंद्रीय कैबिनेट पहुंची डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी की फाइल, महंगाई भत्ते में होगी 3-4 फीसदी की वृद्धि

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दरों में तीन से चार फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए/डीआर की दरों में वृद्धि की फाइल केंद्रीय कैबिनेट की टेबल पर पहुंच चुकी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस फाइल पर मुहर लग सकती है।

पिछले सप्ताह भी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए व डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब दशहरे का त्योहार भी जा चुका है। दिवाली से पहले सरकार, महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दरों में वृद्धि कर कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। वर्तमान में 50 प्रतिशत दर के हिसाब से डीए/डीआर मिल रहा है। बता दें कि डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा, सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्तूबर प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तीन अक्तूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्तूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि, उस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की फाइल नहीं पहुंची थी।

एसआई भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों में परिणाम जारी करने के दिए निर्देश

बिलासपुर. 16 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। कई महीनों से आंदोलन कर रहे एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर स्ढ्ढ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है.

बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के दौरान साल 2018 के अगस्त महीने में कुल 655 पदों के लिए स्ढ्ढ भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) समेत कई अन्य पदों की भर्ती होनी थी. 2019 में सरकार भी बदल गई लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हुई. इसके बाद राज्य की नई सरकार (कांग्रेस) ने साल 2021 के अक्टूबर में 975 पोस्ट के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया था.

एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जून 2022 में शुरू हुई और 8 सितंबर 2023 तक चली. इस दौरान शारीरिक नापजोख जून-जुलाई 2022 में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई, जबकि मुख्य परीक्षा 26 मई से 29 मई 2023 तक हुई. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 से 30 जुलाई 2023 के बीच आयोजित की गई, और अंत में इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 के बीच लिया गया. परीक्षा को पूरा हुए 1 साल से अधिक हो गया, इस बीच एक बार फिर सरकार बदल गई. 2023 में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन अब तक परीक्षा के परीणाम जारी नहीं हुए. परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं. आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, स्वच्छता अभियान और रक्तदान के जरिये कर अभ्यर्थी कई बार रिजल्ट की मांग कर चुके हैं. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है।

मिसल बंदोबस्त पेश नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया खारिज, नए सिरे से जांच की दी छूट

इधर हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा 1950 का मिसल बंदोबस्त पेश नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के आदेश को खारिज किया है. मामले में कोर्ट ने समिति को नए सिरे से जांच करने की छूट प्रदान की है.

दरअसल, बलरामपुर सरगुजा निवासी याचिकाकर्ता विनय प्रकाश एक्का उरांव जाति का है. उन्हें 23 मई 2002 को सरगुजा कलेक्टर कार्यालय से उरांव एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया. याचिकाकर्ता का 30 मई 2005 को शासकीय कॉलेज में पुस्तकालय सहायक के पद पर चयन हुआ. उस समय उसने एसटी उरांव जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था. कॉलेज के प्राचार्य ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने पत्र जारी किया. जाति छानबीन समिति ने 1950 का मिसल बंदोबस्त प्रस्तुत नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की अनुशंसा की थी. इस पर सरगुजा कलेक्टर ने 26 मार्च 2007 को जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया. याचिका पर जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ मिसल बंदोबस्त पेश नहीं होने के आधार पर किसी का जाति प्रनाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अन्य दस्तावेज की जांच की जानी चाहिए. छानबीन समिति किसी व्यक्ति की जाति स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को खारिज किया है. अंग्रेजों ने 1929-30 में पूरे देश की जमीन के इंच-इंच के रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण किया था. इसे ही मिसल बंदोबस्त कहा जाता है. इसी रिकॉर्ड के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार ने जमीनों का प्रबंधन किया. मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद प्रदेश के कई जिलों के मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड गायब हैं.

CMYK